

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': कोई कब्जा नहीं किया था.... (व्यवधान)....

प्रो० रामगोपाल यादव: कब्जे किए गए हैं, इन लोगों ने किए हैं, आज भी किए हैं, मैं लिस्ट दे सकता हूँ कि बीजेपी के लोग और ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम करवा रहे हैं... (व्यवधान)...

श्री सभापति: बस हो गया। Now, it is all right ....(Interruptions)..... Question No. 381—Shri Manohar Kant Dhyani.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों की स्थापना

\*381. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र स्थापित करने की एक योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले सभी विकास केन्द्रों का अनुमोदन कर दिया गया है;

(ग) पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार जिले के लिए स्वीकृत विकास केन्द्र की क्या स्थिति है और यह कब तक कार्य करने लगेगा; और

(घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश को अब तक कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभी पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए विकास केन्द्र योजना वर्ष 1991 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक अवसंरचनात्मक ढांचा प्रदान करना है ताकि इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को आकृष्ट किया जा सके।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश को आवंटित किए गए आठ विकास केन्द्रों में से सात विकास केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित बकाया एक विकास केन्द्र के लिए, राज्य सरकार को अभी स्थान के संबंध में अंतिम निर्णय लेना है और अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करनी है।

(घ) इस योजना के अंतर्गत 2220 लाख रुपए के केन्द्रीय राशि उत्तर प्रदेश को जारी कर दी गई है।

**Setting up of growth centres in the backward areas of U.P.**

†\*381. SHRI MANOHAR KANT DHYANI: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme was approved by Government for the setting up of growth centres in the backward areas;

(b) if so, whether approval has been accorded to all the growth centres to be set up in U.P.;

(c) the status of the growth centre approved for Kotdwar district of Pauri Garhwal and by when it is likely to start functioning; and

(d) the amount which has, so far, been provided to Uttar Pradesh in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) Yes, Sir. The Central Government brought into operation in 1991 the Growth Centre Scheme for setting up Growth Centres in backward areas. The objective of the Scheme is to provide industrial infrastructure to enable these areas to attract industrial units.

(b) and (c) Seven of the eight Growth Centres allotted to Uttar Pradesh have been approved by the Central Government. For the remaining one Growth Centre proposed to be set up in Distt. Pauri Garhwal, the State has yet to finalise the site and submit its detailed project report for approval by the Central Government.

(d) Central release amounting to Rs. 2220 lakhs have been provided under this Scheme to Uttar Pradesh.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश का वह हिस्सा जो अब उत्तरांचल बनने जा रहा है, मेरा प्रश्न उससे संबंधित है। महोदय, उत्तर प्रदेश में कई वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार ने 8 विकास केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया था और इनमें से 7 विकास केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है। यह दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग सत्ता में रहे हैं जिन्होंने जान-बूझकर कोटद्वार में विकास केन्द्र बनने नहीं दिया। अभी मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे अवगत कराया है, शायद उन्हें भी

†Original notice of the question was received in Hindi.

अवगत कराया होगा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार को इस बारे में संस्तुति कर दी है। यहाँ माननीय सिकन्दर बख्त जी बैठे हुए हैं, जब ये इस मंत्रालय में मंत्री थे, तब भी यह प्रश्न उठा था और मुझे यह उत्तर आया था कि यह विकास केन्द्र शीघ्र ही खोला जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोटद्वार का जो विकास केन्द्र है, यह कब तक खुलने वाला है?

डा० रमण: माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश में जो 8 ग्रोथ सेंटर खोलने की सिफारिश की गई थी, उनमें से 7 ग्रोथ सेंटर बचौली, वनथारा, शोदरपुर, विद्यापुर, खुर्जा, सखारिया और सजनवार में स्थापित हो चुके हैं। आठवां ग्रोथ सेंटर जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, इसे पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में खोलने की स्वीकृति दी गई थी। यह चिन्हित किया गया था कि यह ग्रोथ सेंटर पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में खोला जाना है। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने 50 लाख रुपये का प्रोविजनल फंड इसके लिए रिलीज किया। यह पैसा रिलीज करने के बाद परियोजना मूल्यांकन समिति ने 28.5.92 को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार का यह मत पाया कि चूंकि यह भूकंपप्रस्त क्षेत्र है, इसलिए इस ग्रोथ सेंटर को यहां से हटाया जा सकता है, हटाया जाए। यह पहला पत्र 1992 में आया।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि उसके बाद अगस्त 1994 में राज्य सरकार ने निरीक्षण के बाद इस ग्रोथ सेंटर को पौड़ी गढ़वाल में ही बरकरार रखे जाने का प्रस्ताव किया यानी 1992 के बाद 1994 में राज्य सरकार ने दूसरा प्रस्ताव दिया कि इस ग्रोथ सेंटर को वहीं स्थापित किया जाए और केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया। फिर नवंबर 1994 में यह सूचना राज्य सरकार को दे दी गई कि स्थान वही रहेगा, उसके केन्द्र सरकार किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझती है क्योंकि राज्य सरकार से ही इसकी अनुशंसा आई है। महोदय, 26.11.97 को उद्योग मंत्रालय की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा शिवराजपुर में विकास केन्द्र की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई। उस बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों ने यह सूचित किया कि शिवराजपुर-पदमपुर में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। यह बात मुख्य एजेंसी आई०डी०बी०आई० द्वारा भी दोहराई गई। यह जानकारी केन्द्र सरकार को दी गई कि वहां पर जमीन की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। उसके बाद राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल में जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध हो, वहां पर ग्रोथ सेंटर स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव किया। यह सारी प्रक्रिया 1991 से लेकर 1998 तक जारी रही। हम पत्र-व्यवहार करते रहे और उस पत्र-व्यवहार के जवाब में लगातार यही जवाब आता रहा कि वहां पर लैंड की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए वहां पर जमीन ऐक्वायर नहीं की जा रही है। राज्य सरकार ने 8 तारीख तक यही कहा है। मैं माननीय सदस्य को उन पत्रों की जानकारी देना चाहता हूँ जो हमारे विभाग की ओर से जारी किए गए थे, D.O. letter from Secretary, IPP to Chief Secretary, U.P.

सभापति महोदय, 3 अप्रैल, 1998 को हमने एक रिमाइंडर लिखा कि वे जगह तय करें, जमीन ऐक्वायर करें और जमीन ऐक्वायर करने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है, उसके लिए हमको पत्र लिखें ताकि हम यहां से अगली सैक्शन जारी करें। दूसरा पत्र लिखा गया 16 अक्टूबर, 1998 को from Joint Secretary IPP to Chief Secretary, U.P. तीसरा पत्र 10 दिसम्बर, 1998 को लिखा गया from Joint Secretary IPP to Chief Secretary, U.P. चौथा पत्र लिखा गया 21 जून, 2000 को from Joint Secretary IPP to Principal Secretary U.P. इन सारी बातों की समीक्षा होने के बाद मैंने स्वयं एक पत्र वहां के उद्योग मंत्री जी को लिखा कि आप स्थान का चयन करें कि स्थान में परिवर्तन करेंगे या स्थान वही रहेगा, फिर लैंड ऐक्वायर करने के बाद डिटेल्ड प्रपोजल केन्द्र सरकार के पास भेजें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस लैम्बे अरसे में 1991 से आज सन् 2000 में हम खड़े हैं अभी केन्द्र सरकार के पास जो डिटेल्ड प्रपोजल आना चाहिए वह अभी तक नहीं आया है। जिस दिन भी वह प्रपोजल आ जाएगा हम इस योजना के संबंध में बाकी जो राशि है तब उसके बारे में विचार किया जा सकता है जो हमारी योजना है और उस योजना में हम चाहते हैं कि उस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट हो क्योंकि इण्डस्ट्री का मूल विषय-विकास का विषय राज्य सरकारों के ऊपर है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट के लिए, पानी के लिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए और बाकी डवलपमेंट के लिए केन्द्र सरकार हर एक ग्रोथ सेंटर को दस करोड़ की राशि देती है। हम यह राशि देने के लिए आज भी तैयार हैं। यदि वह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास यथाशीघ्र आता है तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इस संबंध में हम तत्काल निर्णय लेकर वह राशि रिलीज कर देंगे।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इस योजना को विलम्बित कराया। उन्होंने यह भी बताया कि वह दस करोड़ की राशि देने के लिए सहमत हैं। तो 1991 में जो दस करोड़ की राशि थी आज उसकी परिस्थिति क्या हो गई है? और इस परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी यह बताएं कि जो आज बढ़ी हुई स्थिति है उस स्थिति में वह राशि बीस करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए वह देने को तैयार है? अब वह जमीन भी मामला नहीं रह गया है। अब चूंकि राज्य बदल गया है-अब उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा उत्तरांचल प्रदेश हो गया है। तो मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इन बदली हुई परिस्थितियों में सदन को बताएं कि यह जो विकास केन्द्र है वह शीघ्र ही कोटद्वार में स्थापित होगा, क्योंकि उन्होंने फिर भी पौड़ी जिला कहा है कोटद्वार का नाम नहीं लिया है जबकि कोटद्वार का नाम तय है, इसलिए वह कोटद्वार के नाम का यहां उल्लेख करके घोषणा करें कि यह शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा?

डा० रमन: डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में शिवराजपुर, पदमपुर में जो स्थान आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें परिवर्तन की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि दस करोड़ की राशि कम पड़ रही है। तो ग्रोथ सेंटर का जो कंसेप्ट था तथा 68 ग्रोथ सेंटर को जो फाइनैस किया जा रहा है, 1991

में जब यह योजना शुरू हुई उस समय की गाईड लाईस के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में हम यह राशि 15 करोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है उसमें दस करोड़ तो केन्द्र सरकार का अनुदान है। एक ग्रोथ सेंटर जो 400 से लेकर 800 हेक्टेयर होता है।.....(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप उनका जवाब सुनिए, जबकि आप उनसे बातें कर रहे हैं।

डा० रमण: उसके लिए 30 करोड़ की राशि लगती है और 30 करोड़ की राशि में स्टेट का शेयर और फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन का जो शेयर होता है यह सब मिला कर और साथ ही साथ जो हम लैंड डवलपमेंट के लिए राशि देते हैं, कुल मिलाकर 30 करोड़ की राशि उस ग्रोथ सेंटर के विकास के लिए मानी जाती है जो 400 से लेकर 800 हेक्टेयर में होता है। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि उस ग्रोथ सेंटर के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तत्काल डिटेल्ड प्रपोजल बनवाकर यहां पर भेजें। पहले योजना आरम्भ हो उसके बाद ही राशि बढ़ाने के बारे में या अन्य विषय पर कोई विचार होगा। मगर मैं तो यह कहना चाहूंगा कि वह प्रपोजल राज्य सरकार से केन्द्र सरकार के पास शीघ्र आए ताकि उस योजना को हम मंजूर कर सकें। इस योजना को मंजूर करने में केन्द्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक महीने में यह प्रस्ताव भेजते हैं तथा हमारे पास डिटेल्ड प्रपोजल आता है तो हम बाकी राशि रिलीज कर देंगे, मैं यह आश्वासन माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लकड़ी का उद्योग, खुर्जा में पोतरी का उद्योग, अलीगढ़ में तालों का उद्योग, आगरा में जूतों का उद्योग और फिरोजाबाद में कांच का उद्योग, सम्भल में जानवरों के सींगों का उद्योग, मुरादाबाद में पीतल उद्योग और इसी तरह से अन्य शहरों में बड़े-बड़े उद्योग ठप्प हो रहे हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से कोताही आ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो उस हिसाब से ये सात सेंटर्स बहुत कम हैं। आप कह रहे हैं कि जमीन की कीमत ज्यादा है। आबादी का घनत्व उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और गांवों से लोग शहरों में जा रहे हैं, इसीलिए जमीन की कीमत बढ़ रही है, हर जगह पर बढ़ रही है, यह कम नहीं हो सकती है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या और अधिक इस प्रकार के केन्द्र खोलने की सरकार की कोई नीति है?

डा. रमण: माननीय सभापति जी, चेयरमैनशिप आफ प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसमें फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के सदस्य और सेक्रेटरीज थे। उस समिति ने पूरे हिन्दुस्तान का सर्वे करने के बाद, स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ चर्चा करके 71 ग्रोथ सेंटर्स आईडेंटिफाई किए। ये ग्रोथ सेंटर्स 1991 में आईडेंटिफाई किए गए। अब नये ग्रोथ सेंटर्स खोलने की बात नहीं हो सकती है जब तक कि फिर से नये सिरे से प्लानिंग कमीशन के साथ और

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के साथ और अन्य जिन लोगों ने इसको रिकमण्ड किया है, उनके साथ इस विषय पर नई चर्चा न हो। आज की तारीख में कोई नया ग्रोथ सेन्टर खोलने की बात नहीं है।

जहां तक छोटे उद्योग की बात है। अलीगढ़ में ताला उद्योग और अन्य उद्योग की बात है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अन्य हमारे पास सेंटर्स हैं, स्माल स्केल सेक्टर के थ्रू और अन्य के थ्रू जो राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसे छोटे उद्योग लगाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करते हैं, उस दृष्टि से हो सकता है। मगर ग्रोथ सेन्टर्स की संख्या कि किस राज्य में कितने ग्रोथ सेंटर्स होंगे, यह तय 1991 में हो चुका था। अब ग्रोथ सेंटर्स की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। अन्य जो योजनाएं हैं, जिनका लाभ अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा सकता है, अलीगढ़ के लिए किया जा सकता है और अन्य क्षेत्र जो माननीय सदस्य ने बताये हैं, उनके लिए किया जा सकता है।

श्री रामदास अग्रवाल: सर, ग्रोथ सेन्टर्स के आपरेशन की योजना 1991 में बनी थी। वैसे जो प्रश्न का पहला भाग है वह जनरल है।...

श्री सभापति: नहीं-नहीं, प्रश्न यू.पी. का है।

श्री रामदास अग्रवाल: ठीक है। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार यू.पी. के संबंध में ही पूछना चाहूंगा। जो सात ग्रोथ सेन्टर्स यू.पी. में लगाए गए हैं, उनके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उनमें कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके हिसाब से उन्होंने अपने ग्रोथ सेन्टर्स के बनने के बाद किस प्रकार की सहायता उद्योगों की की है जिससे उनकी स्थापना का जो लक्ष्य था वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो वह किस रूप में हुआ है, उसकी थोड़ी सी जानकारी दें?

डा. रमण: सभापति जी, माननीय सदस्य ने डिटेल्ड जानकारी पूछी है। संथाला, सजनवा और गंधारा ये तीन ग्रोथ सेंटर्स हैं जहां पर प्लॉट का अलाटमेंट हमने फौरन कर दिया है। जहां पर हमने लैंड एक्वायर कर ली है वह क्षेत्र बिजौरी और खुर्जा हैं। जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे का सवाल है तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 22 करोड़ 20 लाख रुपये आज तक दिए जा चुके हैं और जैसे-जैसे, डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे-जैसे प्लॉट का अलाटमेंट हो रहा है और उनके पास से डिमांड आ रही है वह सारी राशि...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: वर्ष 1991 से लेकर अब तक जो सात सेंटर्स हैं, उनको कितना रुपया दिया है? अगर 22 करोड़ रुपया ही दिया गया है तो यह बहुत कम है जबकि प्रत्येक यूनिट को 10 करोड़ रुपया देना था। इसका मतलब यह हुआ कि उनको 70 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, उसकी जगह पर केवल 22 करोड़ ही दिया गया है तो बाकी की राशि कैसे और कब उनकी उपलब्ध करायी जायेगी?

डा. रमण: सभापति महोदय, राशि उपलब्ध कराना ग्रोथ सेंटरर्स के डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर है। वहां से डिमांड आती है और प्लॉट अलॉटमेंट के बाद राशि दे दी जाती है। अभी जो राशि रिलीज की गई है उसके बारे में माननीय सदस्य को ग्रोथ सेंटरर्सवाइज मैं बताना चाहूंगा। जो हमारे यहां से पैसा रिलीज हुआ है वह बिजौरी में एक करोड़ 50 लाख रुपया और 10 करोड़ की पूरी राशि केन्द्र सरकार की ओर से सजनवा के लिए जारी कर दी गई शिवराजपुर में 50 लाख रुपये की राशि दी गई है, खुर्जा में 4 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि दी गई है, संथारा में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि दी गई है, चौदहपुर में 50 लाख रुपये और गंधारा में 50 लाख रुपये की राशि दी गई है..(व्यवधान)

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय,...

श्री सभापति: नहीं, नहीं, क्रास क्वेश्चनिंग नहीं।

डा. रमण: स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है कि उन्होंने पैसे का उपयोग नहीं किया है, प्लॉट का अलॉटमेंट रुक गया है, प्लॉट के एक्वायरमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो इस वजह से वहां से विलम्ब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पैसे की डिमांड करते हैं हम हर ग्रोथ सेंटर को 10 करोड़ रुपये की पूरी राशि केन्द्र सरकार की ओर से दे देते हैं। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। सवाल यह है कि स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड आने में और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आने में देरी होती है। उसकी वजह से यहां से पैसा जाने में दिक्कत होती है। अगर वह प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज दें तो हर ग्रोथ सेंटर को जो दस करोड़ रुपये देने हैं, उसके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। उसके लिए ही यह पैसा है।

प्रो० राम बख्श सिंह वर्मा: माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि औद्योगिक और संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत सरकार द्वारा ढांचगत कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं और उन सुविधाओं में प्रदेश सरकार का क्या योगदान होता है? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 70 नये केन्द्रों की जो आपने पहचान की है, उनमें कौन-कौन से स्थान हैं तथा दिव्यापुर के लिए कितनी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा अवमुक्त की गयी है?

डा० रमण: सर, माननीय सदस्य ने दिव्यापुर के बारे में बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। राज्य सरकार को अभी तक लैंड ऐक्वीजीशन के मामले में समस्या आ रही है। राज्य सरकार ने अभी तक जमीन ऐक्वायर नहीं की है। सर, प्राइमरी स्टेज में लैंड ऐक्वायर करने के बाद फंड की डिमांड की जाती है इसलिए राज्य सरकार दिव्यापुर के लिए अभी तक राशि की मांग नहीं कर पायी है। महोदय, पहली स्टेज में पचास लाख रुपये दिये जाते हैं, उसको आगे डैवलप करने के लिए पहले लैंड ऐक्वायर किया जाएगा फिर प्लॉट की कटिंग होगी, उसके बाद दूसरी राशि मांगने के संबंध में चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जो दस करोड़ की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा देने का मकसद है, वह उस ग्रोथ सेंटर में इन्फ्रास्ट्रक्चर डैवलप करने के लिए है, खास तौर से पावर,

[21 August, 2000]

RAJYA SABHA

वॉटर, टेली कम्यूनिकेशन, बैंकिंग, सीवेज और बाकी सारी सुविधाएं उस ग्रोथ सेंटर में विकसित हों, इसके लिए यह दस करोड़ की राशि उनको दी जाती है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग को आकर्षित करने के लिए वहां की राज्य सरकार और वहां काम करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनकी जवाबदेही होती है कि उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा विकसित करें। हम यह राशि बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए देते हैं।

*\*382. [The Questioner (Shri Ananta Sethi) was absent for answer vide page 24infra.]*

*\*383. [The Questioner (Shri P. Prabhakar Reddy) was absent, for answer vide page 27infra.]*

*\*384. [The Questioner (Shri S.S. Ahluwalia) was absent, for answer vide page 27infra.]*

#### **Allocation of diesel oil to Rajasthan**

**\*385. SHRI SANTOSH BAGRODIA:** Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) whether Government have allocated diesel oil to Rajasthan;
- (b) if so, the details thereof; and
- (c) the quantity of diesel oil supplied to Rajasthan during the last three years?

**THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK):** (a) and (b) Diesel Oil is supplied through Oil Marketing Companies to meet the full market demand.

(c) The following quantities of diesel oil were supplied to the State of Rajasthan during last three years:—

Year	Quantities in TMT
1997-98	2,420
1998-99	2,557
1999-2000	2,687

**SHRI SANTOSH BAGRODIA:** There is a continuous complaint about supply of diesel; probably, all over the country, but I am confining my question